IV. मुद्राबाहुल्य का नियंत्रण

56. पहले दो विभागों में अनाज की कमी की समस्याओं, औद्योगिक क्रियाकलाप में शिथिलता यानी सुस्ती और इन्हें दूर करने की दिशा में सरकार द्वारा किये जाने वाले उपायों का जिक्र किया गया है। मुख्य रूप से, अनाज की कीमतें बढ़ जाने के कारण, मुद्राबाहुल्य को नियन्त्रण में रखने के लिए कुछ और उपाय करना जरूरी था जिनकी चर्चा इस विभाग में की गयी है।

क. मूल्य-वृद्धि और सम्भावनाएं

57. 1966–67 को समाप्त हुए तीन वर्षों में, मूल्यों में लगभग 12 प्रतिशत के वार्षिक अनुपात से वृद्धि हुई। वर्ष के शुरू में, चालू वर्ष में मूल्यों में और तेजी से वृद्धि होने की सम्भावना को मान लिया गया, क्योंकि इस वृद्धि का मुख्य दबाव अनाज और दूसरे खाद्य पदार्थों पर था और दो वर्षों तक सूखा पड़ने के बाद इन वस्तुओं की कमी साफ तौर पर दिखायी दे रही थी। उस समय जब देश को कठिन परिस्थितियों

का सामना करना पड़ रहा था, नीति सम्बन्धी ज्यादा जोर बाहर से यथासम्भव अधिक से अधिक अनाज मंगाने के लिए शीघ्रता से प्रबन्ध करने और सरकारी माध्यमों द्वारा उनके वितरण की व्यवस्था करने पर था, ताकि मुद्राबाहुल्य की शक्तियों का मुकाबला किया जा सके। साथ ही सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के खर्चों पर भी नियन्त्रण रखना पड़ा, ताकि मांग के दबाव को नियन्त्रित रखा जा सके। बजट इस प्रकार तैयार किया गया जिससे घाटे की अर्थ-व्यवस्था न करनी पड़े। इस्तेमाल में आने वाली कुछ ऐसी वस्तुओं पर और भी कर लगाये गये, जिनका निर्यात भी किया जा सकता है और ऐसा प्रयत्न भी किया गया कि बढ़ते हुए मूल्यों को देखते हुए, सरकारी कर्मचारी पहले से अधिक महंगाई भत्ते की रकमें को ठहर-ठहर कर लेना स्वीकार कर लें और इसमें सरकार को कुछ सफलता भी मिली। अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम (एसेंशियल कमोडिटीज़ ऐक्ट) में संशोधन किया गया, ताकि मूल्य-नियन्त्रण सम्बन्धी उपायों को और अधिक कारगर ढंग से अमल में लाया जा सके और इसके अलावा, अनौपचारिक नियन्त्रण का क्षेत्र भी और अधिक बढ़ा दिया गया। यद्यपि लगातार दूसरे वर्ष भी सूखा पड़ने और चीजों की सप्लाई में कमी होने के कारण मूल्यों के स्तर में और भी तेजी से वृद्धि हो सकती थी, लेकिन उपर्युक्त उपायों से, कम कामकाज के मौसम में मूल्य-वृद्धि को 10 प्रतिशत के अन्दर ही सीमित रखा गया, जो पहले के दो वर्षों में हुई वृद्धि के बराबर है।

58. आलोच्य वर्ष की दूसरी छमाही में, फसल अच्छी होने से मूल्य सम्बन्धी स्थिति में सुधार हुआ है और इसलिए बजट सम्बन्धी खर्चों को नियन्त्रण में रखने के साथ-साथ मुद्रा सम्बन्धी नीति को कुछ और उदार बनाना आवश्यक और सम्भव हो गया।

59. चालू वर्ष की मूल्य सम्बन्धी प्रवृत्तियों की उल्लेखनीय बातें ये हैं :—(i) लगभग अक्टूबर के मध्य तक अन्न और खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में भारी तेजी और उसके बाद गिरावट; (ii) औद्योगिक कच्चे माल, खास तौर पर कच्चे जूट के मूल्यों में गिरावट की प्रवृत्ति—यद्यपि मध्यवर्ती उत्पादनों के मूल्यों के सम्बन्ध में यह प्रवृत्ति कुछ कम रही—जिससे इन वस्तुओं के मूल्यों का औसत स्तर उस स्तर तक नीचे आ गया जहां वह एक वर्ष पहले था; और (iii) कुल मिला कर निर्मित वस्तुओं यानी तैयार माल की कीमतों में उल्लेखनीय स्थिरता (देखिए चार्ट)। ये प्रवृत्तियां पिछले वर्ष सूखा पड़ने और वर्ष के अन्तिम महीनों में काफी अच्छी फसल होने की सम्भावनाओं की द्योतक हैं। निर्मित वस्तुओं के मूल्यों में जो स्थिरता बनी रही वह अंशतः देशी और विदेशी दोनों प्रकार के माल के अपेक्षाकृत आसानी से मिलने और अंशतः कुछ प्रकार की निर्मित वस्तुओं, खास तौर पर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं, मोटर गाड़ियों और कुछ पूंजीगत सामान की मांग कम होने के कारण थी।

60. परन्तु मूल्यों में होने वाले सभी परिवर्तनों के सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता कि ये कृषि पदार्थों की पूर्ति में हुए परिवर्तन और अर्थ-व्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में कामकाज की शिथिलता के कारण हुए। मूल्यों में होने वाले कुछ परिवर्तन, स्पष्टतः सरकारी नीति के परिणाम थे। थोक मूल्यों के सूचक अंक में "शराब और तम्बाकू" वर्ग के अन्तर्गत जो वृद्धि हुई, उसका कारण 1967–68 के बजट में सिगरेटों पर उत्पादन-शुल्क का बढ़ाया जाना था; और "ईंधन, विद्युतशक्ति (पावर), विद्युत प्रकाश (लाइट) और चिकनाने के पदार्थ" वर्ग के अन्तर्गत जो वृद्धि हुई, वह लगभग सारी की सारी पेट्रोलियम

थोक मूल्य

1952—53=100

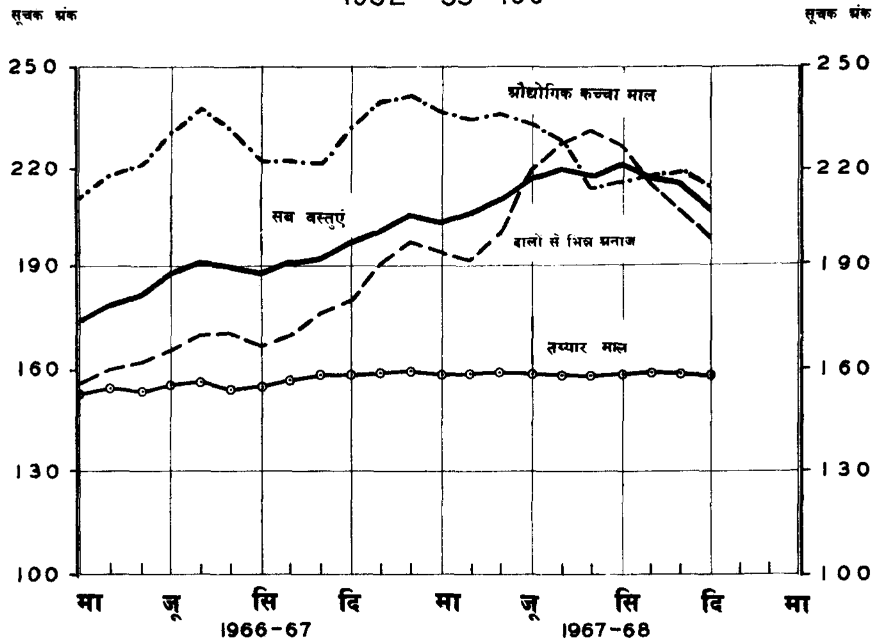

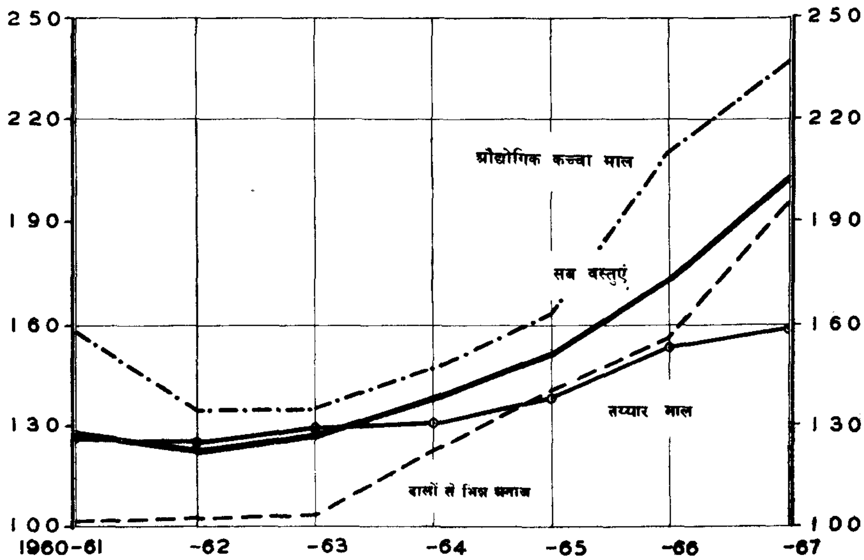

वित्त मंत्रालय, अर्थ प्रभाग

से बने पदार्थों पर लगने वाले करों में हुई वृद्धि और इससे भी अधिक 24 जुलाई, 1967 से विनियन्त्रण के बाद से कोयले के मूल्यों में हुई वृद्धि के कारण थी। अभी हाल में, गेहूं के लिए दी जाने वाली राज-सहायता समाप्त कर दी गयी है और अन्य प्रकार के अनाज पर दी जाने वाली राजसहायता भी काफी कम कर दी गयी है; जनवरी के पहले सप्ताह में अन्न के मूल्य बढ़ने का यही कारण है। सरकार ने अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिए जो विशेष कार्रवाई की, उससे भी निर्मित वस्तुओं के मूल्यों में स्थिरता लाने में सहायता मिली। बढ़ती हुई लागत को देखते हुए, अप्रैल में, नियन्त्रित किस्मों के कपड़े के मूल्यों को बढ़ाने की अनुमति दे दी गयी थी, लेकिन तब से किसी और वृद्धि की अनुमति नहीं दी गयी है। 1968 के शुरू से सीमेण्ट के मूल्यों पर फिर से नियन्त्रण लगा दिया गया है। लेकिन सरकार ने मुख्यतः अन्न के बाजार में ही हस्तक्षेप किया, जिसकी चर्चा विभाग II में की गयी है।

61. हाल में मूल्यों में जो कमी हुई है (मध्य अक्टूबर और दिसम्बर के अन्त के बीच की अवधि में लगभग 7.5 प्रतिशत), उसके कारण मूल्यों का स्तर अब पिछले वर्ष की अपेक्षा लगभग 5.7 प्रतिशत ही ऊंचा है। दिसम्बर 1967 को समाप्त होने वाले तीन महीनों में, चावल के थोक मूल्यों में मौसमी तौर पर 15 प्रतिशत, गेहूं के थोक मूल्यों में 12 प्रतिशत और ज्वार के थोक मूल्यों में 5 प्रतिशत की कमी हुई। इस सम्बन्ध में गेहूं के मूल्यों में हुई कमी विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि यह अवधि ऐसी है जिसमें गेहूं का तोड़ा रहता है। बिहार में चावल की कीमतें, जिनमें पिछले वर्ष बहुत तेजी आ गयी थी, कम हो गयी हैं; गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी चावल की कीमतें गिर गयी हैं। बहुत से राज्यों में, दिसम्बर 1967 के अन्त में, चावल के मूल्य एक वर्ष पहले के मूल्यों से कम थे। आशा है कि मूल्यों में होने वाली यह मौसमी कमी लगभग मार्च या अप्रैल 1968 तक जारी रहेगी। हाल में केवल 1964-65 में ही अच्छी फसल हुई थी और उस वर्ष अनाज के मूल्यों का सूचक अंक, जो सितम्बर 1964 के अन्त में 159 था, बराबर गिरता ही चला गया और मई 1965 के अन्त में 140 तक पहुंच गया। चालू वर्ष में अनाज के मूल्यों का सूचक अंक अगस्त के अन्त में 242 से गिर कर दिसम्बर के अन्त में 211 तक पहुंच गया और भविष्य में इसके और भी गिरने की सम्भावना है। चावल के मूल्यों में हुई कमी 1964-65 की तुलनात्मक अवधि में हुई कमी की अपेक्षा अधिक है। यद्यपि मार्च 1968 के अन्त तक के मूल्यों के सामान्य स्तर के विषय में, पहले से सही-सही अनुमान लगाना कठिन है, लेकिन विश्वासपूर्वक यह आशा की जा सकती है कि थोक मूल्यों का सामान्य सूचक अंक, जो दिसम्बर के अन्त तक गिर कर 207 तक पहुंच गया है, लगभग 205 हो जायगा अर्थात् यह मार्च, 1967 के अन्त तक के स्तर से लगभग केवल एक प्रतिशत अधिक होगा। परन्तु 1967-68 में मूल्यों का औसत स्तर 1966–67 के स्तर की अपेक्षा फिर भी लगभग 11.5 प्रतिशत अधिक ही रहेगा।

62. थोक मूल्यों की वृद्धि खुदरा मूल्यों में प्रायः पूरी तरह से प्रकट होती थी। अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक, जो मार्च, 1967 में 200 था, धीरे-धीरे बढ़ कर अक्टूबर में 217 तक पहुंच गया। हाल में थोक मूल्यों में कमी होने के कारण, जल्दी ही इस सूचक अंक के स्थिर होने

की आशा है; दिसम्बर में यह अंक कम हो कर 214 तक पहुंच चुका है। सरकारी कर्मचारियों और कई उद्योगों के कर्मचारियों को इसी सूचक अंक के आधार पर महंगाई भत्ता दिया जाता है। अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक में, जो इतनी तेजी से वृद्धि हुई उसके कारण 1967 में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तीन बार बढ़ाना पड़ा। पहली फरवरी, 1967 और पहली जून, 1967 से महंगाई भत्ते में जो दो बार वृद्धि की गयी उसके अन्तर्गत सरकार को कुल 53 करोड़ रुपये की अतिरिक्त अदायगी करनी थी, जिसमें से 29 करोड़ रुपया नकद दिया गया और बाकी कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में जमा कर दिया गया।

ख. बजट सम्बन्धी नीति

63. चालू वर्ष में केन्द्रीय सरकार और राज्य-सरकारों की बजट सम्बन्धी स्थिति का बिगड़ना ऊपर कही बात को बल प्रदान करता है, हालांकि उसका कारण, राजस्व की कमी रहा है, न कि बजट अनुमानों की अपेक्षा व्यय का बढ़ जाना। बढ़ते हुए मूल्यों को देख कर, केन्द्र में सन्तुलित बजट पेश करने की कोशिश की गयी थी लेकिन केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बजटों को एक साथ लेने पर, वास्तव में काफी घाटा होने की सम्भावना दिखाई देती है। बजट में हुए घाटे से पता चलता है कि अर्थ-व्यवस्था में शिथिलता की प्रवृत्तियां थीं जिनसे सरकार के राजस्व पर असर पड़ा; क्रियान्वित की जा रहीं प्रायोजनाओं पर असर डाले बिना, सरकारी खर्च में ज्यादा कमी नहीं की जा सकती थी; खर्च कम करने के लिए उन प्रायोजनाओं के निर्माण का कार्यक्रम फिर से निर्धारित करना पड़ता। यदि सरकारी खर्च में और ज्यादा कमी कर दी जाती, तो शिथिलता की प्रवृत्तियों को और भी बल मिलता।

64. केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बजटों में, विकास सम्बन्धी और विकास से भिन्न परिव्यय में 1967-68 में लगभग पांच-पांच प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान किया गया था। वृद्धि की गति, विकास से भिन्न परिव्यय की वृद्धि की गति में, पहले के दो वर्षों के मुकाबले, काफी कमी होने की द्योतक थी। लेकिन विकास सम्बन्धी परिव्यय की आयोजित वृद्धि, लगभग उतनी ही थी जितनी 1966–67 में थी, हालांकि यह वृद्धि, 1965–66 के मुकाबले काफी कम थी :

सारणी—5
केन्द्रीय सरकार और राज्य-सरकारों का व्यय

	प्रतिशत वृद्धि		
	1964–65 के मुकाबले 1965-66 में	1965–66 के मुकाबले 1966-67 के (संशोधित अनुमान)	1966–67 (संशोधित अनुमान) के मुकाबले 1967-68 के (बजट अनुमान)
विकास–सम्बन्धी व्यय . . .	17.3	5.3	5.5
विकास से भिन्न व्यय . . .	19.3	19.0*	5.4

*लेखा-सम्बन्धी लेनदेनों को छोड़ कर।

65. सरकारी परिव्यय पर यह नियन्त्रण रख कर और अतिरिक्त कर लगा कर इच्छित सन्तुलन स्थापित किया जा सकता था। लेकिन अन्ततः असन्तुलन होने का मुख्य कारण यह है कि बजट सम्बन्धी प्राप्तियों, खास कर आयात-शुल्कों, और विदेशी सहायता की प्राप्तियों और सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के अधिशेष में काफी कमी रही और राज्यों की बजट सम्बन्धी स्थिति भी पहले से खराब हो गयी। चालू वर्ष की पहली छमाही में, कुल आयात का स्तर तो पिछले मास की पहली छमाही के मुकाबले ज्यादा न था, पर आयात की जाने वाली वस्तुओं में ऐसी तबदीली हुई जिसका आयात-शुल्कों के संग्रह पर असर पड़ता है। पहले के मुकाबले ऐसी वस्तुओं के आयात का अनुपात बहुत ज्यादा रहा, जिन पर कोई शुल्क नहीं लगता था, या जिनके शुल्क की दर बहुत कम थी। इसी तरह की चीजों के आयात में वृद्धि होती रही है। इन वस्तुओं में रासायनिक खाद, गन्धक, राक-फास्फेट और कपास आदि शामिल हैं। मशीनों के आयात में काफी कमी हुई है और यह कमी विदेशी सहायता की कम प्राप्तियों के रूप में भी प्रकट होती है।

66. 1966-67 में राष्ट्रीय आय में हुई अपर्याप्त वृद्धि (यथार्थ प्रति-व्यक्ति आय में वास्तव में कमी हुई) और औद्योगिक क्रियाकलाप की शिथिलता के कारण, गैर-सरकारी बचतों पर कम से कम राजस्व-वर्ष की पहली छमाही में, काफी असर पड़ा। प्रत्यक्ष करों से प्राप्त होने वाले राजस्व पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। बहुत सम्भव है कि केन्द्र और राज्यों के बाजार–ऋणों में जनता का अंशदान (अर्थात् रिजर्व बैंक और राज्य सरकारों से भिन्न पार्टियों द्वारा किया जाने वाला अंशदान) पिछले वर्ष के 169 करोड़ रुपये के वास्तविक अंशदान के मुकाबले, कम रहे। छोटी बचतों के संग्रह में भी बहुत कमी रही है। इन प्रवृत्तियों से, आमदनी और बचतों की धीमी वृद्धि के मिले-जुले प्रभाव का और मूल्य-वृद्धि की संभावनाओं का पता चलता है।

67. गैर-सरकारी बचतों और निवेश के आज तक के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन इन दोनों में कमी होने के उन संकेतों के अलावा, जिनका जिक्र ऊपर किया गया है, अन्य संकेत भी मिलते हैं। नये शयरों का बाजार मन्दा रहा और शेयर बाजार के मूल्य, पिछले वर्ष की अस्थायी वृद्धि के बाद, फिर गिर गये। 1966-67 में समाप्त हुए पांच वर्षों में, दीर्घकालीन वित्त-व्यवस्था करने वाली वित्तीय संस्थाओं के भुगतानों में तेजी से वृद्धि हुई, लेकिन चालू वर्ष में, इनकी गति कुछ हद तक धीमी हो जाने के संकेत मिलते हैं। 1966-67 में केन्द्रीय सरकार ने इन संस्थाओं के लिए 65 करोड़ रुपये की व्यवस्था की थी, पर उसमें कमी कर दी गयी है और चालू वर्ष में 40 करोड़ रुपये (बजट अनुमान) की ही व्यवस्था की गयी है।

68. मांग कम होने और लागत बढ़ने के कारण, सरकारी क्षेत्र के रेलों समेत विभिन्न प्रतिष्ठानों के कामकाज पर असर पड़ा, जिसका परिणाम यह हुआ कि वर्ष के दौरान, इन उद्यमों के अधिशेषों में कमी हो गयी है और कुछ को बहुत घाटा भी हुआ है।

69. सरकारी क्षेत्र के साधनों और बचतों की प्रवृत्तियों पर विचार करते हुए, यह याद रखना जरूरी है कि साल के ज्यादातर हिस्से में बचतों और साधनों की स्थिति, पिछले वर्ष की सूखे की स्थिति,

शिथिलता और वर्ष के पूर्व भाग की मूल्य वृद्धि से प्रभावित रही। राजस्व वर्ष 1967-68 में, कुल मिला कर, एक दूसरी ही स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि राष्ट्रीय आय में बहुत कुछ वृद्धि होने की सम्भावना है और उसी के साथ-साथ गैर-सरकारी बचतों और निवेशों में काफी वृद्धि हो जायगी। इसमें सन्देह नहीं कि चालू वर्ष की दूसरी छमाही में ही सामान में काफी ज्यादा पूंजी लग जायगी और इसमें से ज्यादातर पूंजी की व्यवस्था सम्भवतः गैर-सरकारी बचतों से की जायगी और कुछ की पूंजी की व्यवस्था बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों से की जायगी।

ग. मुद्रा सम्बन्धी स्थिति

70. वर्ष की मुद्रा-सम्बन्धी स्थिति की विशेषता यह रही कि मुद्रा उपलब्धि की वृद्धि की गति धीमी पड़ गयी। 1965-66 में जनता की मुद्रा-उपलब्धि में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी; 1966-67 में वृद्धि का अनुपात घट कर 8 प्रतिशत रह गया और चालू वर्ष में वृद्धि की गति सम्भवतः और ज्यादा धीमी पड़ जायगी। 19 जनवरी, 1968 तक वृद्धि का वार्षिक अनुपात 7.6 प्रतिशत हो गया था, जो 20 जनवरी, 1967 तक के अनुपात (9.6 प्रतिशत) से बहुत कम था।

71. चालू वर्ष में अब तक मुद्रा-उपलब्धि में हुई घट-बढ़ सारणी 6 में दिखलायी गयी है। उस सारणी में पिछले वर्ष का तुलनात्मक चित्र भी उपस्थित किया गया है। बैंकों द्वारा केन्द्रीय सरकार और राज्य-सरकारों को दिये जाने वाले वास्तविक ऋणों में 31 मार्च, 1967 से 12 जनवरी 1968 तक की अवधि में 345 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। यह इस अवधि में मुद्रा-उपलब्धि की वृद्धि का मुख्य कारण था। रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिये जाने वाले ऋणों की रकम इस वर्ष अब तक, पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले, काफी कम रही है। रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्रीय सरकार को दिये जाने वाले ऋणों के सम्बन्ध में यह बात खास तौर से सही है। रिजर्व बैंक के सम्बन्ध में राज्य सरकारों की स्थिति की खराबी सारणी में दिखाये गये आंकड़ों से स्पष्ट हो जाती है। इस सारणी में दिखायी गयी प्रवृत्तियां वर्ष के एक भाग के सम्बन्ध में ही हैं; उन्हें पूरे वर्ष की सम्भाव्य स्थिति का द्योतक मानना ठीक नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर, यह सम्भव है कि जैसे ही ज्यादा कामकाज के मौसम में कामकाज बढ़ने लगेगा, वाणिज्यिक बैंक अपने पास रखी सरकारी प्रतिभूतियों खालकर राजकोष हुण्डियों को रिजर्व बैंक से भुनाना चाहेंगे। अब तक रिजर्व बैंक द्वारा इस तरह की हुण्डियों के फिर से भुनाये जाने के काम की रफ्तार सामान्य रफतार से कम रही है। इस वर्ष के शुरू में, जमा रकमों की वृद्धि की गति धीमी रही, पर हाल में वह गति फिर से तेज हो गयी है। फिर भी, पिछले वर्ष के मुकाबले, मीयादी जमा की रकमों की वृद्धि कम रही (रकम के रूप में भी और अनुपात के रूप में भी)।

72. यद्यपि 1967–68 में मुद्रा-वृद्धि का अनुपात लगभग उतना ही रहा, जितना 1966-67 में था, फिर भी यह अनुपात राष्ट्रीय उत्पादन की प्रत्याशित वृद्धि के अनुपात से कम रहेगा, पर वास्तविक राष्ट्रीय उत्पादन में 1966–67 और 1967–68 में हुई वृद्धि के अनुपातों के औसत से ज्यादा रहेगा। (मुद्रा वृद्धि के अनुपात को वास्तविक उत्पादन की वृद्धि के अनुपात के साथ मिलाकर

देखने की अपेक्षा इस प्रकार की तुलना प्रायः ज्यादा उपयोगी होती है, क्योंकि किसी भी निर्दिष्ट राजस्व-वर्ष में पूर्ति की स्थिति अंशतः उससे पहले के फसली वर्ष की फसल सम्बन्धी स्थिति पर निर्भर रहती है)।

73. बैंकों के साधनों की मौसमी घट-बढ़ और उन साधनों के इस्तेमाल की प्रणाली परिशिष्ट की सारणी 4.2 में दिखायी गयी है। 1966–67 के अधिक कामकाज के मौसम में ऋण-संबंधी वृद्धि उससे पहले के अधिक कामकाज के मौसम की तुलना में, काफी ज्यादा रही। चूंकि अधिक कामकाज के मौसम के शुरु में, फसलें आशा से कम हुईं इसलिये, रिजर्व बैंक ऋण-नियंत्रण के उन उपायों को लागू करने के लिए, जो अधिक कामकाज के मौसम के शुरू में लागू किये गये थे, मौसम के अन्त में हस्तक्षेप किया। मूल्यों पर बराबर पड़ने वाले दबाव को देखते हुए, 1967 के कम कामकाज के मौसम में, ऋणों की मात्रा में पर्याप्त कमी करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया। इस तरह की आयोजित कमी से, अधिक कामकाज के अगले मौसम की आवश्यकताओं को पूरा करने में बैंकों की स्थिति और अधिक सुविधाजनक हो जायगी। बैंकों को कम कामकाज के मौसम में भी पहले जारी किये गये अधिक कामकाज के मौसम के सम्बन्ध में लागू होने वाले उस निदेश के तत्व पर अमल करने की सलाह दी गयी जिसके अनुसार उन्हें ऋण-वृद्धि के मामले में औद्योगिक अग्रिमों को तरजीह देनी चाहिए। उनसे यह भी कहा गया कि वे जमा रकमों को जुटाने के लिए भी ठोस प्रयत्न करें।

सारणी—6

मुद्रा उपलब्धि में घट-बढ़

(करोड़ रुपयों में)

	1966-67 31 मार्च से 31 मार्च तक	1966-67 31 मार्च से 13 जनवरी तक	1967-68 31 मार्च से 12 जनवरी तक
1. बैंकों द्वारा सरकार को दिया गया वास्तविक ऋण (क+ख)	278*	322*	345*
क. रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया ऋण [(क)+(ख)]	**195***	**196***	**175**
(क) केन्द्रीय सरकार को दिया गया ऋण [(1)+(2)+(3)−(4)]	333*	246*	139
(1) रुपया-प्रतिभूतियां	217*	19*	21

(करोड़ रुपयों में)

	1966-67 31 मार्च से 31 मार्च तक	1966-67 31 मार्च से 13 जनवरी तक	1967-68 31 मार्च से 12 जनवरी तक
(2) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खरीदी और भुनायी गयी हुण्डियां . . .	112	154	56
(3) रुपया–सिक्का . . .	—16	—11	—1
(4) केन्द्रीय सरकार की जमा रकम .	—19	—84	—63
(ख) राज्य-सरकारों को दिया गया ऋण [(1) –(2)]	—138	—51	36
(1) राज्य-सरकारों को दिये गये ऋण और अग्रिम	—126	—70	5
(2) राज्य-सरकारों की जमा रकम	12	—19	—31
ख. बैंकों के पास सरकारी प्रतिभूतियां . .	83	126	170
2. बैंकों द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र को दिया गया वास्तविक ऋण [(क)–(ख)] .	182	—25	—103
(क) अग्रिम और गैर-सरकारी प्रतिभूतियां (बैंकों द्वारा दिया गया कुल ऋण) . .	427	233	135
(ख) मीयादी जमा . . .	246	258	238
3. रिजर्व बैंक की वास्तविक विदेशी-मुद्रा परिसम्पत्ति	—23*	—64*	—40
4. जनता को मुद्रा-उपलब्धि . .	377	186	181
(क) जनता के पास मुद्रा (करेंसी) .	142	77	75
(ख) जनता की जमा रकमें . .	235	109	106

*रुपये के सम-मूल्य में परिवर्तन होने के बाद, रिज़र्व बैंक की परिसम्पत्ति के किये गये पुनर्मूल्यन को छोड़कर।

टिप्पणी: (1) रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिये गये ऋण के जो आंकड़े ऊपर की सारणी में दिये गये हैं, वे सरकार द्वारा रिजर्व बैंक को चुकाये जाने वाले कर्ज की घट-बढ को सूचित करते हैं। लेकिन, राजस्व वर्ष का हिसाब-किताब, राजस्व वर्ष की समाप्ति के कुछ दिन बाद ही पूरी तरह से समायोजित किया जाता है। ऊपर दिये गये आंकड़ों में रिजर्व बैंक के पास रखे रुपयों के सिक्कों की रकम की घट-बढ़, रिजर्व बैंक द्वारा जनता से खरीदी और भुनायी गयी हुण्डियों और रिजर्व बैंक के पास रखी दीर्घावधिक रुपया–प्रतिभूतियों की रकम की घटबढ़ जैसी मदें शामिल कर ली गयी है। इसलिए रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिये गये ऋण के जो आंकड़े यहां दिखलाये गये हैं वे बजट-पत्रों में दिखाये गये, बजट–सम्बन्धी घाटे के आंकड़ों से भिन्न हैं।

(2) सम्भव है, कि पूर्णांकन के कारण, आंकड़ों का जोड़, दिये गये जोड़ से न मिले।

74. अर्थ-व्यवस्था में पैदा हुई सुस्ती की प्रवृत्तियों के संदर्भ में, कम कामकाज के मौसम में, बाद में ऋण नीति के रुख में थोड़ा परिवर्तन किया गया। कृषि, निर्यात, इंजीनियरी उद्योगों, छोटे उद्योगों और सड़क परिवहन के प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को ऋण देने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अगस्त, 1967 में ऋण नीति-संबंधी अनेक उपायों की घोषणा की गयी। इरादा यह था कि इस बात की पक्की व्यवस्था हो जाय कि पर्याप्त धन के अभाव के कारण उत्पादन की वृद्धि के रास्ते में कोई रुकावट न आने पाये (इन उपायों का विवरण समीक्षा में अन्यत्र कर दिया गया है)।

75. अन्ततः, अनुसूचित बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों में कम कामकाज के मौसम में जो कमी हुई, वह (रकम के रूप में ज्यादा होने पर भी) पहले के अधिक काम-काज के मौसम में हुई ऋण-वृद्धि को देखते हुए पिछले वर्ष की अपेक्षा कम रही। 1966 में, कम कामकाज के मौसम में हुई ऋणों की कमी, उससे पहले के अधिक कामकाज के मौसम में हुई वृद्धि के 28 प्रतिशत भाग के बराबर रही; 1967 में यह वृद्धि 24 प्रतिशत थी। संभव है कि यह स्थिति आंशिक रूप में ऋण-संबंधी उन उपायों के कारण हुई हो जो शिथिलता की स्थिति का मुकाबला करने के लिए किये गये थे। यह भी महत्वपूर्ण है कि बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों में इस वर्ष के सितम्बर और अक्टूबर में, पिछले वर्ष के इन्हीं महीनों के मुकाबले, काफी ज्यादा वृद्धि हुई (27 करोड़ रुपये के मुकाबले 58 करोड़ रुपये)।

सारणी—7

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिया गया ऋण

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष के अन्त में	बकाया	घट-बढ़
1966 अप्रैल	2329	..
अगस्त	2217	−112
अक्टूबर	2244	27
1967 अप्रैल	2670	426*
अगस्त	2510	−160
अक्टूबर	2568	58

*यह रकम अधिक कामकाज के पिछले मौसम में हुई ऋण-वृद्धि की द्योतक है।

76. खास-खास मामलों में बैंकों द्वारा उदार शर्तों पर ऋण दिये जाने की जिन व्यवस्थाओं की घोषणा रिजर्व बैंक ने अगस्त 1967 में की थी, उन्हें अधिक काम काज के मौसम में भी लागू रहने दिया गया है। इसके अलावा, रिजर्व बैंक ने, अधिक काम-काज के मौसम के लिए अपनी पुनर्वित्त सुविधाओं को और ज्यादा उदार बनाने की भी घोषणा की। चुना गया तरीका उस तरीके से कुछ भिन्न था, जो अधिक कामकाज के पिछले मौसम में उस समय अपनाया गया था, जब अनुसूचित बैंकों को बैंक-दर पर एक अतिरिक्त रकम अदा की गयी थी। वास्तव में, इस रकम का काफी बड़ा भाग खर्च न किया जा सका, हालांकि इस बात की शिकायतें की जा रही थीं कि बैंकों द्वारा की जाने वाली वित्त-व्यवस्था अपर्याप्त है। इसलिये, अधिक कामकाज के चालू मौसम के लिए, बैंकों को इस बात का संकेत दे दिया गया है कि वे बैंक दर पर जो अतिरिक्त पुनर्वित्त प्राप्त कर सकते हैं, वह राशि के आधार पर नहीं बल्कि प्रयोजन के आधार पर दिया जायगा। उन सब अग्रिमों को, जो राज्य सरकारों या उनके अभिकरणों या अन्न निगम को अनाज की प्राप्ति या उसके वितरण या संग्रह के लिए दिये गये हों, बैंक-दर पर पुनर्वित्त के योग्य बनाया गया। इसी तरह, रासायनिक खादों और हानिकर जीवों का नष्ट करने वाली दवाओं के वितरण की वित्त-व्यवस्था करने के लिए दिये गये अग्रिमों को भी इसके योग्य बना दिया गया। इन अग्रिमों के सम्बन्ध में प्राप्त किये गये पुनर्वित्त की मात्रा में, अक्टूबर, 1967 के स्तर से ऊपर जो वृद्धि होगी उसे बैंकों की वास्तविक नगदी और नगदी जैसी परिसम्पत्ति के अनुपात का हिसाब लगाते समय शामिल नहीं किया जायगा। इसलिए, बैंकों द्वारा तरजीही क्षेत्रों को ऋण दिये जाने के परिणामस्वरूप, गैर-तरजीही क्षेत्रों को अग्रिम देने की उनकी क्षमता कम न होगी। पहले की तरह बैंकों की वास्तविक नगदी और नगदी जैसी परिसम्पत्ति का अनुपात 30 प्रतिशत के आधारभूत न्यूनतम अनुपात से जितना ज्यादा होगा, उतने के संबंध में बैंकों को पुनर्वित्त मिलता रहेगा। बैंक दर पर मिल सकने वाली निर्धारित रकमों से ज्यादा उधार ली गयी सभी रकमों पर ब्याज की और ज्यादा ऊंची दर लागू की जायगी, जो 8 प्रतिशत से कम न होगी, पर बहुत थोड़ी अवधि के लिए ज्यादा से ज्यादा एक सप्ताह तक उधार ली जाने वाली रकमों पर ब्याज की यह ऊंची दर लागू न होगी।

77. इस प्रकार अधिक कामकाज के मौसम की नीति का उद्देश्य यह है कि बैंकों के लिए पर्याप्त साधनों की व्यवस्था की जाये ताकि वे ऋणों की उस बढ़ी हुई मांग को पूरा कर सकें, जिसके, कृषि-उत्पादन की वृद्धि को देखते हुए, पैदा होने का अनुमान है। इस बात की सम्भावना है कि रिजर्व बैंक से ऋण लेने का औसत खर्च, जो ज्यादा कामकाज के पिछले मौसम में लगभग 6.5 प्रतिशत था, उस अधिकतम स्तर से कम हो जायगा। ऋण-नीति को भी पहले से कुछ और ज्यादा लचीला बनाया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, उन विभिन्न बैंकों को विवेक के अनुसार ऋण देने की व्यवस्था भी की गयी है, जिनकी नकदी और नकदी जैसी परिसम्पत्ति पर, कपास, सोयाबीन आदि के आयातों के या अपने असामियों द्वारा की जाने वाली कर की अदायगियों के समूहीकरण जैसे विशिष्ट कारणों से, दबाव पड़ने की आशंका हो। विवेक के आधार पर ऋण देने की व्यवस्था उस समय भी की जायगी, जब कोई बैंक रिजर्व बैंक को यह सूचित करेगा कि वह अपने साधनों पर पड़ने वाले दबाव के कारण, निर्माण करने वाले

उद्योग–धन्धों और कृषि की उचित आवश्यकताओं को पूरा करने की स्थिति में नहीं है । अप्रतिभूत अग्रिमों के वर्ग की परिभाषा बदल दी गयी है और उसमें से उत्पादन के प्रयोजन के लिये दिये जाने वाले कुछ वास्तविक अग्रिमों को निकाल दिया गया है; इसलिये इन अग्रिमों पर ऋण सम्बन्धी ऐसे नियंत्रण नहीं लगेंगे जो अप्रतिभूत ऋणों पर विशेष रूप से लगाये जाते हैं ।

78. अधिक कामकाज के चालू मौसम में अब तक (19 जनवरी तक) ऋण-वृद्धि उससे पहले के अधिक कामकाज के मौसम के मुकाबले कम रही । लेकिन जमा रकमों की वृद्धि की गति पिछले वर्ष के मुकाबले कुछ तेज रही । इसलिए, अब तक मुद्रा-बाजार की स्थिति समुचित रूप से सुविधाजनक रही है और कुल मिलाकर बैंकों को रिजर्व बैंक से उधार नहीं लेना पड़ा है । मांगते ही चुकाये जानेवाले ऋणों की दर 19 जनवरी, 1968 को बम्बई में 4 प्रतिशत थी, जो एक वर्ष पहले की दर से 2 प्रतिशत कम थी ।

79. अधिक कामकाज के चालू मौसम की ऋण की प्रवृत्तियों की समीक्षा करने के बाद, रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को ज्यादा ऋण देने को बढ़ावा देने के उपायों की घोषणा हाल ही में की । निर्यात और खेती के काम आने वाली चीजों (रासायनिक खादों और हानिकर जीवों को नष्ट करने वाली दवाओं) के प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये जाने वाले अग्रिमों में और छोटे पैमाने के उद्योगों को दिये जाने वाले गारण्टी अग्रिमों में हुई वृद्धि के सम्बन्ध में, रिजर्व बैंक से उन बैंकों द्वारा लिये जाने वाले ऋणों पर 4.5 प्रतिशत की रियायती दर लागू की गयी । इस रियायत का उद्देश्य यह था कि रिजर्व बैंक से लिये जाने वाले ऋणों की लागत कम हो जाय और बैंक अपने ग्राहकों को ऋण की ज्यादा अच्छी सुविधाएं प्रदान कर सकें । उदाहरण के लिए, बैंक इस बात पर राजी हो गये हैं कि वे निर्यात के लिए दिये जाने वाले ऋणों पर 8 प्रतिशत के स्थान पर 7.5 प्रतिशत से ज्यादा ब्याज नहीं लेंगे ।

80. मुद्रा सम्बन्धी नीति का उद्देश्य प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों के उत्पादन को पुनः बढ़ाना और निर्यात को बढ़ावा देना है । जहां सामान्य ऋण व्यवस्थाएं मुख्य रूप से उत्पादन और निर्यात की वृद्धि के उद्देश्य से की जा रही हैं, वहां छंटाई के आधार पर किये जाने वाले नियंत्रणों का उद्देश्य अलग-अलग चीजों के आधार पर दिये जाने वाले अग्रिमों की विशिष्ट अधिकतम सीमा और मार्जिन निर्धारित करके मूल्य वृद्धि पर रोक लगाये रखना है । रिजर्व बैंक द्वारा दिये जाने वाले पुनर्वित्त से ऋण सम्बन्धी मौसमी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है । वह हर साल अर्थ-व्यवस्था की बढ़ती हुई ऋण-सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकों द्वारा अपने जमा-साधनों के जुटाये जाने का स्थान ग्रहण नहीं कर सकता ।

81. यद्यपि प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों के लिए ऋण की व्यवस्था की जरूरत बराबर बनी हुई है, पर जिन वर्षों में गैर-सरकारी बचतें कम होती हैं और बैंकों के कुल वित्तीय साधन नाकाफी होते हैं, उन वर्षों

में समस्या और भी उग्र हो जाती है । बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण स्थापित करने की जो नीति इसी साल लागू की गयी है उसका उद्देश्य इस बात को सुनिश्चित करना है, कि अर्थ-व्यवस्था में उपलब्ध ऋण-साधनों को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों के उपयोग मे लाया जाय और उनका उपयोग करने वाले विभिन्न पक्षों में उन का समान रूप से वितरण हो ।

82. सारांश यह कि इस वर्ष हुई मूल्य-वृद्धि, मुख्य रूप से पूर्ति में, खासकर खाद्य पदार्थों की पूर्ति में हुई कमी के कारण हुई । बजट सम्बन्धी असंतुलन बना रहा, हालांकि नीति का उद्देश्य इसके विपरीत था । लेकिन यह असंतुलन ज्यादातर शिथिलता का परिणाम था, मुद्रा–बाहुल्य का कारण नहीं । मूल्य कृषि-पदार्थों की पूर्ति की वृद्धि पर निर्भर है । लेकिन अगले वर्ष में लागत में ज्यादा वृद्धि हो जाने की संभावना है । मुद्रा सम्बन्धी आमदनी में काफी ज्यादा वृद्धि होने से खासकर कृषि के क्षेत्र में यह वृद्धि होने से, मांग का दबाव भी बढ़ेगा । बढ़ी हुई कुल मांग का दबाव स्वतः अर्थ–व्यवस्था के उन क्षेत्रों पर नहीं पड़ेगा जिनमें अतिरिक्त उत्पादन-क्षमता हो । इसलिए मूल्यों की स्थिति पर बराबर नजर रखने की जरूरत है।